

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क/बी-6/नियमन/एफपीओ/628/691

भोपाल, दिनांक 19/10/2020

प्रति,

संयुक्त /उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय..... (समस्त)

विषय:-एग्रीकल्चर इन्फ्रा स्टीक्चर फण्ड योजना अंतर्गत कृषक, (FPOS, PACS) मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉपरेटिव सोसाइटी आदि को लाभान्वित करने के संबंध में।

संदर्भ:- प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का मेल दिनांक 23 सितम्बर 2020

विषय संदर्भ में लेख है कि प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से एग्रीकल्चर इन्फ्रा स्टीक्चर फण्ड योजना अंतर्गत कृषक, (FPOS, PACS) मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉपरेटिव सोसाइटी आदि को लाभान्वित करने के संबंध में मेल प्राप्त हुआ है। जिसके साथ भारत सरकार कृषि मंत्रालय किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली का पत्र दिनांक 17.7.20 के साथ उनकी स्कीम गाईडलाइन संलग्न की गई है। छायाप्रति संलग्न है।

कृपया भारत सरकार की स्कीम गाईडलाइन के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्ताव मुख्यालय को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

(अपर संचालक महोदय के निर्देशानुसार)



संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Fwd: एग्रीकल्चर इन्फ्रा स्ट्रीकचपर फण्ड योजना अंतर्गत कृषक, (FPOS, PACS, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉपरेटिव सोसाइटी) आदि को लाभान्वित करने बावत्।

1 message

Principal Secretary Horticulture & Food Processing, Mantralaya <pshort@mp.gov.in>
To: mdmandiboard@gmail.com

Wed, Sep 23, 2020 at 5:14 PM

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्रमांक <u>ml/5075</u> तिथिंक <u>23-09-2020</u>
शाखा <u>AD(नियमन)</u>

प्रबंध निदेशक

From: "Principal Secretary Horticulture & Food Processing, Mantralaya" <pshort@mp.gov.in>

To: "commrewa" <commrewa@nic.in>

Sent: Wednesday, September 23, 2020 5:11:04 PM

Subject: Fwd: एग्रीकल्चर इन्फ्रा स्ट्रीकचपर फण्ड योजना अंतर्गत कृषक, (FPOS, PACS, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉपरेटिव सोसाइटी) आदि को लाभान्वित करने बावत्।

निम्नः
संबंधित कार्य को
कम से कम
आदि आदि
R
A

From: "Principal Secretary Horticulture & Food Processing, Mantralaya" <pshort@mp.gov.in>

To: "Commissioner Office, Indore" <commindore@nic.in>, "commgwa" <commgwa@mp.nic.in>, "Commissioner Jabalpur Div" <commjabalpur@mp.nic.in>, "Commissioner Narmadapuram" <commnarmadapuram@mp.gov.in>, "Commissioner Sagar" <commsagar@nic.in>, "Commissioner Shahdol" <commshahdol@mp.gov.in>, "commujjain" <commujjain@mp.nic.in>, "Mr Ravindra Mishra" <commchambal@nic.in>, "Dy.Agriculture Production Commissioner Bhopal." <dyapcbho@mp.gov.in>, "Sh. Kavindra Kiyawat" <commbho@nic.in>

Cc: "dirhort" <dirhort@nic.in>, "mpagrohobpl" <mpagrohobpl@gmail.com>

Sent: Wednesday, September 23, 2020 5:05:26 PM

Subject: Fwd: एग्रीकल्चर इन्फ्रा स्ट्रीकचपर फण्ड योजना अंतर्गत कृषक, (FPOS, PACS, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉपरेटिव सोसाइटी) आदि को लाभान्वित करने बावत्।

4020 24-9-20
ए.डी. (फिरोस)/पी.ए. क.
इत्त प्रवि

From: "Principal Secretary Horticulture & Food Processing, Mantralaya" <pshort@mp.gov.in>

ab
A

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1310/1410/2020/58,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 /09/2020

कलेक्टर,
जिला समस्त (म.प्र.)

विषय:- एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना अंतर्गत कृषक, (FPOS, PACS, मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी) आदि को लाभान्वित करने बावत्।

संदर्भ:- भारत सरकार कृषि मंत्रालय किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक R-11016/2/2020-I&P दिनांक 17.07.2020

भारत सरकार कृषि मंत्रालय किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक R-11016/2/2020-I&P दिनांक 17.07.2020 के द्वारा एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है। इस योजना के तहत कृषक, (FPOS, PACS, मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी) आदि को लाभान्वित किया जाना है।

- 2/ इस योजना के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये।
 - i. योजना हेतु Viable Projects तैयार किये जाये।
 - ii. योजना का प्रचार-प्रसार आई.ई.सी. (Information Education and Communication), कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK), एवं Webinar आदि के माध्यम से किया जाये।
 - iii. उक्त योजना के अन्तर्गत अधोसंरचना का चयन (कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेम्बर, पैक हाउस, प्याज भण्डार गृह, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट आदि) One District One Product scheme के तहत प्रदेश के जिलों में चयनित फसलों के आधार पर किया जाये।
 - iv. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों (FPOS, PACS, मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी) आदि का www.agriinfra.dac.gov.in वेबसाईट पर ऑनलाईन पंजीयन कराये।
- 3/ इस संबंध में One District One Product की अवधारणा के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के निम्न जिलों में चयनित फसलों हेतु परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया जाना है:-

क्र.	जिले का नाम	चिन्हित उत्पाद	प्रस्तावित परियोजना का प्रकार
1	आगरमालवा, राजगढ़	संतरा	ग्रेडिंग एण्ड सॉर्टिंग यूनिट
2	अलीराजपुर	सफेद मूसली	प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट
3	अनूपपुर, बालाघाट, सीधी, उमरिया	आम	राइपनिंग चेम्बर, मोबाइल पलपिंग यूनिट
4	अशोकनगर, गुना	धनिया	ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एण्ड ड्राईंग यूनिट

निरंतर.....

क्र.	जिले का नाम	चिन्हित उत्पाद	प्रस्तावित परियोजना का प्रकार
5	बड़वानी, दमोह, धार, सागर, सतना, झाबुआ, कटनी, रायसेन, शिवपुरी	टमाटर	प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, मोबाइल पलपिंग यूनिट
6	बेतूल	काजू	प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट
7	भिण्ड, छिन्दवाड़ा, देवास, ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन, इन्दौर	आलू, सरसों	कोल्ड चैन, कोल्ड स्टोरेज
8	भोपाल, श्योपुर	अमरूद	प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, मोबाइल पलपिंग यूनिट
9	बुरहानपुर	केला	राइपनिंग चेंबर, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट
10	छतरपुर, रीवा, शहडोल,	हल्दी	ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा
11	जबलपुर	हरी मटर	कोल्ड चैन, कोल्ड स्टोरेज
12	मन्दसौर, रतलम, दतिया	लहसुन	ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा
13	पन्ना	आंवला	ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा
14	हरदा, खरगौन	मिर्च	ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज
15	होशंगाबाद	नींबू, अमरूद	ग्रेडिंग एण्ड सॉर्टिंग यूनिट
16	शाजापुर, खण्डवा	प्याज	ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा
17	टीकमगढ़, निवाड़ी	अदरक	ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा

कृपया उक्त योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ हितग्राहियों को दिलाने हेतु योजना के प्रावधान अनुसार सभी आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

K. Mani
(कल्पना श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

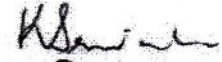
निरंतर.....

क्रमांक 1311 /1410/2020/58,

भोपाल, दिनांक 23/09/2020

प्रतिलिपि:- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड), मध्यप्रदेश भोपाल।
7. आयुक्त, संभाग, मध्यप्रदेश।
8. कलेक्टर जिला, मध्यप्रदेश की ओर उक्त निर्देशों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला, मध्यप्रदेश।
10. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग (समस्त), मध्यप्रदेश।
11. उप/सहायक संचालक उद्यान जिला, मध्यप्रदेश।
12. आई.टी. शाखा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपडेट व साईट पर लिंक करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

No. R-11016/2/2020-I&P
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

New Delhi, dated 17th July, 2020;
Krishi Bhawan, New Delhi

To,

Chief Secretaries of all States/UTs

Subject:- Operational Guidelines of Central Sector Scheme of " Financing Facility under
Agriculture Infrastructure Fund"

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 16.07.2020 on the subject cited above vide which decision of the Government of India to launch the new pan India Central Sector Scheme of " Financing Facility under Agriculture Infrastructure Fund" was communicated and to say that Operational Guidelines of the above mentioned Scheme are enclosed.

2 It is requested that wide publicity to the scheme may kindly be given and successful implementation of the scheme may be ensured. Timely progress of the scheme can be shared with the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare.

Enclosure- As above

Yours faithfully,


(K.R. Meena)
Director (CPC)
Tel.23386224

Distribution :-

1. Secretary, Department of Expenditure, North Block, New Delhi
2. Secretary, Department of Financial Services, Jeevandeep Building, New Delhi.
3. Secretary, Department of Economic Affairs, North Block, New Delhi
4. Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi.
5. Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Sri Fort Village, August Kranti Marg, New Delhi.
6. Secretary, Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi
7. PAMD, Niti Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi
8. Principal Secretary Agriculture of all States/UTs
9. Principal Secretary Cooperation of all States / UTs

10. Registrar Cooperative Societies of all States / UTs
11. Reserve Bank of India
12. All Scheduled Commercial Banks
13. All State Cooperatives Banks
14. All District Cooperative Banks
15. All Regional Rural Banks/Small Finance Banks/Non-Banking Financial Companies (NBFCs)
16. MD, National Cooperative Development Corporation (NCDC)
17. NIC, DAC&FW to upload on website of the Department
18. PS to Hon'ble Agriculture Minister
19. PS to Hon'ble MOS, Agriculture & Farmers Welfare
20. PPS to Secretary, DAC&FW
21. PPS to SS&FA, DAC&FW
22. All Divisional Heads of DAC&FW
23. Guard File

Copy also for kind information to:-

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Principal Secretary to PM, PMO, South Block, New Delhi.



**Scheme Guidelines
for
CENTRAL SECTOR SCHEME
of
Financing facility under 'Agriculture Infrastructure Fund'**

Scheme Guidelines

**Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
Government of India**

Index

S.No.	Particulars	Page No.
1	Introduction	3
2	Rationale of the Scheme	3-4
3	Objectives of Scheme	4-5
4	Implementation Period of Scheme	5
5.	Government Budgetary Support	5-6
6.	Eligible Projects	6-7
7.	Size of the financing facility& eligible beneficiaries	7
8.	Participating institutions	7
9.	Refinance	7
10.	Cap on lending rate	7-8
11	Project Management and handholding support	8
12.	Convergence	8
13.	Revisit of the Scheme	8
14	Monitoring framework	9
15	Output and outcome monitoring framework (OOMF)	9
16	Linkage with PFMS	9
17	Criteria for selection of eligible borrower	9
18	VGF requirement	9
19	Sector specific focus	9
20	States specific focus	10

Scheme Guidelines for CENTRAL SECTOR SCHEME of financing facility under 'Agriculture Infrastructure Fund'

1. Introduction

The role of infrastructure is crucial for agriculture development and for taking the production dynamics to the next level. It is only through the development of infrastructure, especially at the post harvest stage that the produce can be optimally utilized with opportunity for value addition and fair deal for the farmers. Development of such infrastructure shall also address the vagaries of nature, the regional disparities, development of human resource and realization of full potential of our limited land resource.

In view of above, the Hon'ble Finance Minister announced on 15.05.2020 Rs 1 lakh crore Agri Infrastructure Fund for farm-gate infrastructure for farmers. Financing facility of Rs. 1,00,000 crore will be provided for funding Agriculture Infrastructure Projects at farm-gate & aggregation points (Primary Agricultural Cooperative Societies, Farmers Producer Organizations, Agriculture entrepreneurs, Start-ups, etc.). Impetus for development of farm-gate & aggregation point, affordable and financially viable Post Harvest Management infrastructure.

Accordingly, DAC&FW has formulated the Central Sector Scheme to mobilize a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects relating to post-harvest management Infrastructure and community farming assets through incentives and financial support.

2 Rationale of theScheme

Agriculture and allied activities are the primary income source for ~58% of total population of India. ~85% of the farmers are Small Holding Farmers (SHFs) with less than 2 hectares of land under cultivation and manage ~45% of agricultural land. Annual income of majority of the farmers is very low. Further, India has limited infrastructure connecting farmers to markets and hence, 15-20% of yield is wasted which is relatively higher vs. other countries where it ranges between 5-15%. Investment in agriculture in India has further been stagnant with less than 2% CAGR over last 5 years. Investment in FY17 was ~ Rs. 2.19 lac crore out of which private sector share was ~83% vs. a higher investment of ~ Rs. 2.50 lac crore in FY14 and a higher share of private sector at ~88%. Also, lack of investor confidence is leading to lower plowback ratio (~14% of Gross Value addition in FY18) vs. other sectors (~33% of Gross

Value addition in FY18).

3 Objectives of Scheme

Tomobilize a medium - long term debt finances facility for investment in viable projects for post-harvest management Infrastructure and community farming assets through incentives and financial support in order to improve agriculture infrastructure in the country. This financing facility will have numerous objective for all the stakeholders in the agriculture eco-system.

- a. Farmers (including FPOs, PACS, Marketing Cooperative Societies, Multipurpose cooperative societies)
 - Improved marketing infrastructure to allow farmers to sell directly to a larger base of consumers and hence, increase value realization for the farmers. This will improve the overall income of farmers.
 - With investments in logistics infrastructure, farmers will be able to sell in the market with reduced post-harvest losses and a smaller number of intermediaries. This further will make farmers independent and improve access to market.
 - With modern packaging and cold storage system access, farmers will be able to further decide when to sell in the market and improve realization.
 - Community farming assets for improved productivity and optimization of inputs will result in substantial savings to farmers.
- b. Government
 - Government will be able to direct priority sector lending in the currently unviable projects by supporting through interest subvention, incentive and credit guarantee. This will initiate the cycle of innovation and private sector investment in agriculture.
 - Due to improvements in post-harvest infrastructure, government will further be able to reduce national food wastage percentage thereby enable agriculture sector to become competitive with current global levels.
 - Central/State Government Agencies or local bodies will be able to structure viable PPP projects for attracting investment in agriculture infrastructure.
- c. Agri entrepreneurs and startups

- With a dedicated source of funding, entrepreneurs will push for innovation in agriculture sector by leveraging new age technologies including IoT, AI, etc.
- It will also connect the players in ecosystem and hence, improve avenues for collaboration between entrepreneurs and farmers.

d. Banking ecosystem

- With Credit Guarantee, incentive and interest subvention lending institutions will be able to lend with a lower risk. This scheme will help to enlarge their customer base and diversification of portfolio.
- Refinance facility will enable larger role for cooperative banks and RRBs.

e. Consumers

- With reduced inefficiencies in post-harvest ecosystem, key benefit for consumers will be a larger share of produce reaching the market and hence, better quality and prices. Overall, the investment via the financing facility in agriculture infrastructure will benefit all the eco-system players.

4 Implementation Period of Scheme

The Scheme will be operational from 2020-21 to 2029-30. Disbursement in four years starting with sanction of Rs. 10,000 crore in the first year and Rs. 30,000 crore each in next three financial years. Moratorium for repayment under this financing facility may vary subject to minimum of 6 months and maximum of 2 years.

5 Government Budgetary Support

Budgetary support will be provided for interest subvention and credit guarantee fee as also administrative cost of PMU. The details are as below:-

Sl. No.	Name of Component	Norms
1	Interest Subvention Cost	All loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of Rs. 2 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. In case of loans beyond Rs.2 crore, then interest subvention will be limited up to 2 crore. The extent and percentage of funding to private entrepreneurs out of the total financing

		facility may be fixed by the National Monitoring Committee.
2	Credit Guarantee Cost	Credit guarantee coverage will be available for eligible borrowers from this financing facility under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme for a loan up to Rs. 2 crore. The fee for this coverage will be paid by the Government. In case of FPOs the credit guarantee may be availed from the facility created under FPO promotion scheme of DACFW.
3	Administration Cost of PMU	Farmers Welfare Programme Implementation Society under DACFW will provide PMU support to the scheme at the central level and state PMUs of PM KISAN at state level. Services of knowledge partners will be engaged to identify clusters including export clusters and gaps in supply chains to target projects and prepare viable project reports to support the beneficiaries.

6 Eligible Projects

The scheme will facilitate setting up and modernization of key elements of the value chain including

(A) Post Harvest Management Projects like:

- (i) Supply chain services including e-marketing platforms
- (ii) Warehouses
- (iii) Silos
- (iv) Pack houses
- (v) Assaying units
- (vi) Sorting & grading units
- (vii) Cold chains
- (viii) Logistics facilities
- (ix) Primary processing centers
- (x) Ripening Chambers

(B) Viable projects for building community farming assets including –

- (i) Organic inputs production

- (ii) Bio stimulant production units
- (iii) Infrastructure for smart and precision agriculture.
- (iv) Projects identified for providing supply chain infrastructure for clusters of crops including export clusters.
- (v) Projects promoted by Central/State/Local Governments or their agencies under PPP for building community farming assets or post harvest management projects.

7 Size of the financing facility and eligible beneficiaries

Rs. 1 Lakh Crore to be provided by banks and financial institutions as loans to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Marketing Cooperative Societies, Farmer Producers Organizations (FPOs), Self Help Group (SHG), Farmers, Joint Liability Groups (JLG), Multipurpose Cooperative Societies, Agri-entrepreneurs, Startups and Central/State agency or Local Body sponsored Public Private Partnership Projects.

PACS who have adopted digitization for handling its operations will be given preference under this scheme.

8 Participating Institutions

All scheduled commercial banks, scheduled cooperative banks, Regional Rural Banks (RRBs), Small Finance Banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) may participate to provide this financing facility, after signing of Memorandum of Understanding (MoU) with National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD)/DAC&FW.

9 Refinance

If required, need based refinance support will be made available by NABARD to all eligible lending entities including cooperative banks and RRBs as per its policy.

10 Cap on lending rate

Lending rate of participating lending entities will be decided after due consultation with lending entities and same will be circulated to all stake holders. Lending institutions will sign MOU with DAC&FW/ NABARD for implementation of the Scheme. MOUs to be signed by DAC&FW/NABARD with banks/financial institutions with a view that NABARD will negotiate cap on lending rates in a fair manner.

11 Project Management and handholding support

An online platform will be made available in collaboration with participating lending institutions to provide information and loan sanctioning facility. Agri Infra fund will be managed and monitored through an online MIS platform. It will enable all the qualified entities to apply for loan under the fund. The system will also provide benefits such as transparency of interest rates offered by multiple banks, scheme details including interest subvention and credit guarantee offered, minimum documentation, faster approval process as also integration with other scheme benefits. At the back end, the platform will also provide multiple views of dashboards across district, state and national level PMUs to monitor the total sanctioned amount and number of borrowers, total interest subvention benefit availed, loan statement summary, demographic and geographic mix of borrowers and type of projects.

Farmers Welfare Programme Implementation Society under DACFW will provide PMU support to the scheme at the central level and state PMUs of PM KISAN at state level. Services of knowledge partners will be engaged to identify clusters including export clusters and gaps in supply chains to target projects and prepare viable project reports to support the beneficiaries.

Project reports with indicative unit costs will be prepared by Central and State PMUs for guidance of beneficiaries and lending entities. Such project reports shall be available on online platform.

12 Convergence – Any grant or subsidy available under any present or future scheme of Central/State government can be availed for projects under this financing facility. In cases of capital subsidy such amount shall be considered as promoter's contribution. However, a minimum of 10% of the project cost shall be mandatory as promoter's contribution.

13 Revisit of the Scheme

The scheme will be re-visited by Department of Expenditure after disbursement of Rs. 20,000 crores is completed, for evaluation and midcourse correction if required. Concurrent/mid-term third party independent evaluation of the scheme in addition to end- line evaluation will be conducted as and when required.

14 Monitoring framework

The National, State and District Level Monitoring Committees to ensure real-time monitoring and effective feed-back about the implementation of the proposed scheme. The Committees will be set up as per Annexure-A.

All assets created under this financing facility shall be geo tagged. The District Monitoring Committee and respective lending entity shall ensure that updated information on such geo tagged assets is available on the online portal.

15 OUTPUT AND OUTCOME MONITORING FRAMEWORK (OOMF)

The Output and Outcome Monitoring Framework (OOMF) (Annexure-B) will be a part of monitoring system and the measurement of outcome indicators will be monitored periodically by DLMC, SLMC and NLMC.

16 Linkage with PFMS

Interest subvention and credit guarantee support will be released to Banks and lending institutions through PFMS.

Disbursal of funds by lending entities to beneficiaries under this scheme shall be in Aadhaar linked bank account.

17 Criteria for selection of Eligible Borrower

Lending institutions will decide criteria for selection of eligible borrower in consultation with NABARD and monitoring committees, PMUs and keeping in mind the viability of the projects and to avoid NPA.

18 VGF Requirement

In case VGF requirement is projected by central / state / local bodies, norms as prescribed by DEA for PPP projects will be adhered to.

19 Sector specific focus

24% of total grants – in – aid under the scheme should be utilized for SC/ST entrepreneurs (16% for SC and 8% for ST). Besides this, lending institutions would ensure adequate coverage of entrepreneurs belonging to women and other weaker segments of society may be provided loan on priority basis to ensure that benefits of implementation are inclusive and accrued to the intended beneficiaries in accordance with Government guidelines and policies.

20 State specific focus

Tentative State wise allocation of financing facility has been worked out on the basis of the ratio of total value of output of Agriculture and Allied sectors of States/UTs and placed at **Annexure- C**

Monitoring framework

(i) National level Monitoring Committee (NLMC)

Composition :-

Following will be the Members and Chairman of the NLMC:-

- a. Secretary (DAC&FW) (Chairman)
- b. MD SFAC
- c. MD, NCDC
- d. Special Secretary/Additional Secretary and FA (DAC&FW)
- e. Additional Secretary DFS
- f. Additional Secretary (DAC&FW, GoI)
- g. Chairman, NABARD or his representative
- h. Principal Secretary-State Government (s)- Four States by rotation
- i. State Nodal Officers of four States (by rotation)
- j. Joint Secretary (DAC&FW) and CEO of Farmers Welfare Programme Implementation Society- Member Secretary

Functions:-

1. National level Monitoring Committee (NLMC) will guide and steer the implementation of the project. It will approve the guidelines for implementation of the project.
2. National level Implementation Committee (NLIC) will examine and recommend the guidelines for implementation of the project. It also will ensure and review the implementation of the scheme as per approved guidelines by the National level Monitoring Committee (NLMC)

(ii) State level Monitoring Committee

Composition:-

Following will be Members and Chairman of the SLMC :-

- a. Chief Secretary –Chairman
- b. Agriculture Production Commissioner/Principal Secretary Agriculture
- c. Principal Secretary (Cooperation)
- d. Registrar of Cooperative Societies (RCS)

- e. Chief General Manager (CGM), NABARD
- f. Regional Director, NCDC
- g. Officers nominated by State (not more than three).
- h. SLBC Convenor.
- i. State Nodal Officer- Member Secretary.

Functions:-

1. State level Monitoring Committee (SLMC) will implement the NIMC guidelines at the state level and provide feedback to NIMC.
2. It will also guide and steer the implementation of the scheme in the state.
3. It will also examine and approve the selected list of beneficiaries/ projects for inclusion in the scheme in consultation with DLMC
4. It will set the targets as per OOMF format and review the progress regularly

(iii) District Level Monitoring Committee

Composition:-

Following will be Members and Chairman of the DLMC:-

- a. District Collector – Chairman
- b. Chief Executive Officer of District Panchayat/CDO- Vice Chairman
- c. District Officer of Agriculture
- d. District Registrar Officers nominated Cooperative Societies
- e. Officers nominated by State (not more than three)
- f. Lead District Manager of DLBC
- g. District Manager NABARD- Member Secretary

Functions:-

1. District level Monitoring Committee (DLMC) The DLMC will be the first line of implementation and monitoring system within the overall framework.
2. It will identify the beneficiaries, to ensure viability of the project and prepare viable project reports to support the beneficiaries in collaboration with PMU.
3. It will also examine the proposal and recommend to SLMC for consideration.
4. DLMC will set targets in consultation with SLMC as per OOMF format and monitor the progress closely with the support of PMU.
5. DLMC will maintain the Dashboard in collaboration with PMU.

6. It will be responsible for the smooth implementation of the scheme and resolve any issues at the district level. In the process of sorting out implementation issues the Committee would be supported by the district administration wherever required.

OOMF Framework

OUTPUTS:

Output statement	Output Indicators	Target	Achievement
Promoting creation and modernization of agriculture infrastructure	No. of projects submitted by eligible entities		
	Disbursement of funds for eligible projects/investments (Rs. Crores)		
Increase in amount of interest subvention and credit guarantee support provided	Amount outgo on account of interest subvention (Rs. Crore)		
	No. of projects receiving interest subvention		
	Percent projects receiving interest subvention (of the total projects offered loan under the scheme)		
	Amount outgo on credit guarantee coverage (Rs. Crore)		
	Average percent credit guarantee coverage of the total credit extension under the scheme.		

OUTCOMES:

Outcome Statement	Outcome Indicators	Target	Achievement
Improvement in resource provision for agriculture infrastructure	Percentage of fund utilized for completed projects		
	Additional investments leveraged due to agriculture infrastructure fund interventions (Rs. Crore)		
Enhancement in agriculture infrastructure capacity	Total capacity addition in agriculture sector due to infrastructure activities funded (MT)		
	Reduction in post-harvest losses and food wastages (%)		

Tentative Allocation of Financing Facility among States/UTs

Sl. No.	State	Financing Facility INR Crore
1	Uttar Pradesh	12831
2	Rajasthan	9015
3	Maharashtra	8460
4	Madhya Pradesh	7440
5	Gujarat	7282
6	West Bengal	7260
7	Andhra Pradesh	6540
8	Tamil Nadu	5990
9	Punjab	4713
10	Karnataka	4525
11	Bihar	3980
12	Haryana	3900
13	Telangana	3075
14	Kerala	2520
15	Odisha	2500
16	Assam	2050
17	Chhattisgarh	1990
18	Jharkhand	1445
19	Himachal Pradesh	925
20	Jammu & Kashmir & Ladakh	900
21	Uttarakhand	785
22	Tripura	360
23	Arunachal Pradesh	290
24	Nagaland	230
25	Manipur	200

26	Mizoram	196
27	Meghalaya	190
28	Goa	110
29	Delhi	102
30	Sikkim	56
31	Puducherry	48
32	A & N Islands	40
33	Daman & Diu	22
34	Lakshadweep	11
35	Dadra & Nagar Haveli	10
36	Chandigarh	9
	Total	1,00,000